23-02-2024

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र प्रायोजित योजना यानी "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम " को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव को कुल 4,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के दो घटक हैं -
- कुल 2940 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ FMBAP के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) वाले घटक के तहत बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी व्यवस्था के विकास और समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। सामान्य श्रेणी के राज्यों में किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त प्रबंधन 60 प्रतिशत (केन्द्र) और 40 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण पद्धति 90 प्रतिशत (केंद्र) और 10 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में रहेगी।
- कुल 1160 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ F M B A P के नदी प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के तहत पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमा पर स्थित साझी नदियों पर जल विज्ञान संबंधी अवलोकन एवं बाढ़ के पूर्वानुमान सहित बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव-रोधी कार्यों और सीमा पर स्थित साझी नदियों पर संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओंकी जांच व निर्माण-पूर्व गतिविधियों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ शामिल किया जाएगा।
- ध्यान रहे, बाढ़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाढ़ प्रबंधन में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देना, आधुनिक प्रौद्योगिकी

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

एवं नवीन सामग्री/दृष्टिकोण को बढ़ावा देने व अपनाने को प्रोत्साहित करना वांछनीय है।

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के बारे में

- वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (Flood Management and Border Areas Programme-FMBAP) को मंज़ूरी दी थी।
- इस कार्यक्रम को बाढ़ प्रबंधन कार्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों तथा कार्यों हेतु पूरे देश में लागू किया गया है।
- FMBAP योजना को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMP) तथा नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (River Management Activities and Works related to Border Areas-RMBA) नामक दो स्कीमों के घटकों को आपस में विलय करके तैयार की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, भू-क्षरण पर नियंत्रण के साथ-साथ समुद्र तटीय क्षेत्रों के क्षरण के रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करना है|
- यह योजना देश में बाढ़ और भू-क्षरण से शहरों, गाँवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार नेटवर्क, कृषि क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचों आदि को बचाने में मदद करेगा। साथ ही जलग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में गाद कम करने में सहायता मिलेगी।
- इस योजना के तहत पड़ोसी देशों के साथ साझा नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं जैसे- नेपाल में पंचेश्वर तथा सप्तकोसी-सनकोसी परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जाँच-पड़ताल एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि तैयार करना भी शामिल है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में संशोधन की मंजूरी दी, जो निम्नलिखित है -
- निजी कंपनियों, व्यक्तियों, स्टार्ट-अप / एसएचजी / एफपीओ / एफसीओ / जेएलजी / किसान सहकारी समितियों (एफसीओ) को घोड़ा गधा, खच्चर, ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना हेतु 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा घोड़े, गधे और ऊंट के नस्ल संरक्षण के लिए राज्य सरकार को सहायता एवं इन नस्लों के वीर्य स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ रूपए की सहायता दी जाएगी।
- इन कंपनियों को चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा भंडारण गोदाम) सहित बुनियादी ढांचे की स्थापना जैसे भवन निर्माण, रिसीविंग शेड, ड्राईंग प्लेटफॉर्म, मशीनरी आदि के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा बैंक वित्त या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से की जाएगी|

- चारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि / चरागाहों / गैर कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ वन भूमि "गैर-वन बंजर भूमि/चरागाहों/गैर-कृषि योग्य भूमि" और "वन भूमि से चारा उत्पादन" के साथ-साथ निम्नीकृत वन भूमि में भी चारे की खेती के लिए सहायता दी जाएगी।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

- पशुधन बीमा कार्यक्रम को सरल बनाया गया है। किसानों के लिए प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा कम कर दिया गया है और यह मौजूदा लाभार्थी हिस्से 20प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत होगा। प्रीमियम की शेष राशि केन्द्र और राज्य द्वारा सभी राज्यों के लिए 60:40, 90:10 के अनुपात में साझा की जाएगी।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के बारे में

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) को 2014-15 में चार उप-मिशन के साथ शुरू किया गया था
  - (i) चारा और चारा विकास पर उप-मिशन
  - (ii) पशुधन विकास पर उप-मिशन
  - (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुअर वृद्धि पर उप-मिशन
  - (iv) कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन।
- इस योजना को 2021-22 के दौरान फिर से व्यवस्थित किया गया और 2300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विकास कार्यक्रम के तहत जुलाई, 2021 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया।
- ध्यान रहे, वर्तमान में नये सिरे से तैयार किये गए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) में तीन उप-मिशन हैं।
  - (i) पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल सुधार पर उप-मिशन
  - (ii) चारा और चारा का उप-मिशन और
  - (iii) नवाचार और विस्तार पर उप-मिशन। नये सिरे से तैयार एनएलएम में उद्यमिता विकास, चारा और चारा विकास, अनुसंधान और नवाचार, पशुधन बीमा की ओर 1 0 गतिविधियां और लक्ष्य हैं।

सम्मक्का-सरक्का मेदारम जथारा त्योहार

सुर्खियों में क्यों?

- 21 फरवरी, 2024 को एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला सम्मक्का -सरक्का जथारा तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू हुआ | चार दिवसीय मेदाराम जथारा उत्सव कन्नेपल्ली गांव से सरक्का की मूर्ति के पारंपरिक आगमन के साथ शुरू हुआ।
- इसके शुभारंभ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाएं दी तथा मोदी ने सम्मक्का-सरक्का को श्रद्धांजलि अर्पित करके उनकी एकता और वीरता के आदर्श की भावना का स्मरण किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- सम्मक्का सरक्का जथारा, जिसे मेदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है, देवी-देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है।
- मेदाराम जतारा कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला और एशिया के सबसे बड़े जनजातीय मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय-कोया जनजाति द्वारा चार दिनों तक मनाया जाता है।
- यह मेदाराम जथारा देवी सम्मक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह दो साल में एक बार 'माघ' (फरवरी) महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

- यह शासक शासकों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक माँ और बेटी, सम्मक्का

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

और सरक्का की लड़ाई की याद दिलाता है। सरलाम्मा सम्मक्का की बेटी थी। उनकी मूर्ति, अनुष्ठानों के अनुसार, मेदाराम के पास एक छोटे से गाँव कन्नेपल्ली के एक मंदिर में स्थापित की गई है।

- सम्मक्का की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। एक आदिवासी कहानी के अनुसार, लगभग 6-7 शताब्दी पहले, 13वीं शताब्दी में, शिकार करने गए कुछ आदिवासी नेताओं को एक नवजात लड़की (सम्मक्का) मिली जो बाघों के बीच खेल रही थी और भारी रोशनी छोड़ रही थी। वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए, और जनजाति के मुखिया ने उसे सरदार के रूप में अपनाया। बाद में वह इलाके के आदिवासियों की रक्षक बन गईं|
- उनका विवाह काकतीय के एक सामंती आदिवासी प्रमुख पागिदिद्दा राजू से हुआ था, जिन्होंने 1000 ईस्वी और 1380 ईस्वी के बीच वारंगल शहर से आंध्र प्रदेश पर शासन किया था।

जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को रोग मुक्त बनाना है | इससे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे बीमारियों की रोकथाम पर जोर देने के साथ उनके स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में सुधार और सुरक्षा की जा सके।

- आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषद सीसीआरएएस के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईसीएमआर-एनआईआरटीएच जबलपुर की संयुक्त पहल से जनजातीय विद्यार्थियों के लिए यह स्वास्थ्य पहल शुरू की है।
- इसकी घोषणा सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए संयुक्त पहल के रूप में की गई है। इस परियोजना से 20,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ होगा।
- इस परियोजना का लक्ष्य देश के 14 राज्यों में चिन्हित 55 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में छठी से 12वीं कक्षा में नामांकित 10-18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को कवर करना है।
- यह पहल जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का अध्ययन करने तथा आयुर्वेद के माध्यम से कुपोषण, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और सिकल सेल रोगों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पूरा करने में सहयोग करेंगे।
- ध्यान रहे, जनजातीय विकास के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2022 में आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के अनुसार सीसीआरएएस ने 20 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 72 पोषण वाटिकाएं विकसित कीं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में

- `एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्याल (ईएमआरएस) की शुरुआत 1997-98 में की ग

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

थी। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

- स्कूल न केवल शैक्षणिक शिक्षा पर बल्कि अच्छे स्वास्थ्य सहित छात्रों के समग्र विकास पर फोकस करते हैं। इन स्कूलों का फोकस खेल और कौशल विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं पर है।
- वर्तमान में देश भर में 401 कार्यात्मक स्कूल हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2024 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

INDUS-X शिखर सम्मेलन

सुर्खियों में क्यों?

- 20-21 फरवरी, 2024 को रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रयास के रूप में INDUS-X शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है|

INDUS-X के बारे में

- भारत-अमेरिका डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम, जिसे INDUS-X के नाम से भी जाना जाता है, को जून 2023 में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था।
- इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और रक्षा विभाग (DoD) के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस
- (iDEX) द्वारा यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के संयोजन में किया जाता है।
- इंडस-एक्स शिखर सम्मेलन एक दो दिवसीय कार्यक्रम है जो उभरते अवसरों का पता लगाने और उनका लाभ उठाने के लिए दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाता है।
- शिखर सम्मेलन में सहयोग, नवाचार और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई गतिविधियों की एक गतिशील श्रृंखला पेश की गई है।
- यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और रणनीतिक साझेदारी के लिए मंच तैयार करता है। यह अंतर-राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नेटवर्क को उत्तेजित करता है और घरेलू उद्यमियों, बाजारों, कौशल संस्थानों, सरकारी प्रयोगशालाओं और निवेश पूंजी के बीच संपर्क का मुद्दा बनाता है, जो सफल नवाचार के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)